

उत्तर प्रदेश नई सोशल मीडिया पॉलिसी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य [फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब](#) सहित सभी प्लेटफॉर्मों पर सामग्री को वनियमिति करना है।

मुख्य बंदि

- नई सोशल मीडिया पॉलिसी के अनुसार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने प्लेटफॉर्म पर सरकार की योजनाओं और पहलों को साझा करके प्रति माह 8 लाख तक की आय अर्जित कर सकते हैं।
 - देश के वभिन्न भागों एवं वदिशों में रह रहे राज्य के नवासियों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध कराना सुनश्चिति कथिा जाएगा।
- सूत्रों के अनुसार, लसिटगि के लथि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइबर तथा फॉलोअर्स के आधार पर चार श्रेणियों में वभिजति कथिा गया है।
 - एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम के खाताधारकों या ऑपरेटर्स अथवा प्रभावितों को भुगतान के लथि श्रेणीवार अधकितम भुगतान सीमा क्रमशः 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए प्रति माह नरिधारति की गई है।
 - यूट्यूब पर वीडियो, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट भुगतान के लथि श्रेणीवार अधकितम भुगतान सीमा क्रमशः 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए प्रति माह तय की गई है।
- सरकार ने वजिआपनों को संभालने के लथि एक डजिटल एजेंसी 'V-फॉर्म' को सूचीबद्ध कथिा है। यह वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील दखिाने के लथि ज़मिमेदार होगी।
- नीति में आपत्तजिनक [सोशल मीडिया सामग्री](#) से नपिटने के लथि दशिा-नरिदेश भी प्रसतुत कथिा गए हैं।
 - सोशल मीडिया पर [राष्ट्रवसिधी](#), [असामाजकि](#), [फेक न्यूज़](#) या भडकाऊ सामग्री पोस्ट करने पर कारयवाही की जाएगी।